



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशास्त्र द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 सितम्बर, 1993/ 16 चादपद, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

आदेश

शिमला-2, 4 सितम्बर, 1993

संख्या 11-1/66 (लैब) आई० डी०.—चूंकि जनरल सेक्टर, हिमाचल होटल मजदूर लाल ब्रंडा यूनियन (सम्बन्धित सीटू) बाबा बिल्डिंग, सैट नं० 9, दी माल शिमला-3 द्वारा दिनांक 3-5-93 को निम्न मांग-पत्र उठाया था :—

1. वर्तमान वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाये ।
2. उत्सव भत्ता एक माह के वेतन के बराबर दिया जाये ।
3. जिन कामगारों को आवास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है उन्हें मकान किराया दिया जाये ।
4. गर्म तथा ठंडी बर्दियां समस्त कामगारों को दी जाये ।
5. समस्त होटलों में भविष्य निधि स्कीम लागू की जाये ।
6. समझौते के अनुसार सभी प्रबन्धक कामगारों को बर्वाईयां नहीं दे रहे हैं अतः एसोसियेशन समझौते को लागू करवाये ।
7. समस्त कामगारों को पहचान पत्र दिए जायें ।

चूँकि यूनियन ने मांगों को 10 दिनों के अन्दर स्वीकार करने के लिये अनुरोध किया साथ में सूचित किया कि यदि उनकी मांगें समय पर नहीं मानी गईं तो उन्हें मांगें मनवाने के लिए अन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसकी जिम्मेवारी प्रबन्धक पक्ष की होगी ;

और चूँकि लाल शंडा यूनियन से सम्बन्धित कर्मचारी 18-5-93 से हड़ताल पर है ;

और चूँकि समझौता बैठकें समझौता अधिकारी एवं श्रम अधिकारी, शिमला द्वारा विभिन्न तिथियों में रखी गईं लेकिन दोनों पक्षों में समझौता न हो सका ;

और जब कि समझौता अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई कि विवाद को न्यायाधिक निर्णय के लिये श्रम न्यायालय को भेजा जाये ;

और चूँकि उपरोक्त औद्योगिक विवाद न्यायाधिक निर्णय के लिये श्रम न्यायालय को सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 19 तथा 23-8-93 को भेज दिये गये ;

चूँकि हड़ताल से पर्यटन उद्योग को हानि हो रही है ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(3) में सरकार द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त यूनियन द्वारा उक्त विवाद में की जा रही हड़ताल को तत्काल जनहित में निषिद्ध किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-
शमायुक्त ।